राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के विकास संबंधी योजना

3498. श्री एम० एस० पुरती : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार द्वारा 464 कोयला खानो के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उनके विकास तथा उत्पादन क्षमता बढाने सम्बन्धी कोई योजना बनाई गई है, और

(ख) यदि हा, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हसदा) : (क) और (ख) सरकार ने, कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 के अधीन, इन कोयला खानो का, उनका राष्ट्रीयकरण होने तक, हाल ही मे प्रबंध ग्रहण किया है । खानो के पुनर्गठन की प्रायोजना विचाराधीन है । खानो को उचित रूप से सगठित किये जाने के पश्चात् ही उनके विकास के लिए विस्तृत प्रायोजनाए तैयार की जायेगी ।

बंगलादेश के प्रधान मंत्री की यू० एन० ओ० को सहायतार्थ अपील

3499. श्री एम० एस० पुरती
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बगला देश मे राहत की समस्या के 1973 मे अधिक कठिन होने के समाचार मिले हैं

(ख) क्या बगलादेश के प्रधान मत्री ने सयुक्त राष्ट्र सघ से सहायतार्थ अपील की है ; और

(ग) सहायतार्थ सामने आने वाले देशो के नाम क्या हैं और भारत ने बगलादेश को कितनी सहायता देने का वचन दिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) प्राप्त समाचारो के अनुसार बगलादेशमे राहत तथा पुनर्वास के काम मे काफी प्रगति हुई है । लेकिन बगलादेश की मुख्य फसल जो हाल ही मे काटी गई है, सन्तोषजनक नही रही है ।

(ख) बगला देश के प्रधान मत्री ने 14 अक्तूबर, 1972 को सयुक्त राष्ट्र सघ के महासचिव को एक पत्र भेजा है जिसमे उन्होंने 1973 के दौरान सयुक्त राष्ट्र सहायता कार्य की आवश्यकता के बारे मे लिखा है ।

(ग) हमे सूचना मिली है, उसके अनुसार सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यू० के०, जर्मन सघीय गणराज्य, स्वीडन, नार्वे, आस्ट्रेलिया तथा जापान ने 1973 के दौरान सहायता का प्रस्ताव रखा है ।

1971–72 तथा 1972–73 के वित्तीय वर्षों मे भारत द्वारा बगलादेश को दो सौ करोड रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसकी सूचना सदन मे पहले ही दी गई है । आशा है कि इस रकम का कुछ हिस्सा 1973–74 के वित्तीय वर्ष के लिए बच जायेगा तथा 1973–74 मे खर्च होगा ।